



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 19, बुधवार, शाके 1941 - जुलाई 10, 2019
Asadha 19, Wednesday, Saka 1941- July 10, 2019

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.44.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची IV में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची IV केभाग ख - औद्योगिक इनपुट्स के प्रवर्ग के अधीन माल में, विद्यमान क्रम संख्यांक 183 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-24]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.45.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची VI में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची VI में, विद्यमान क्रम संख्यांक 24 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 25 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"	25.	द्रवीय या गैसीय स्थिति में प्राकृतिक गैस	10	"
---	-----	------------------------------------------	----	---

[प.12(43)वित्त/कर/2019-25]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.46.-राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा,

- (i) उसके स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से; और
- (ii) राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (कनेक्टिविटी एण्ड नेट-मीटरिंग फॉर रूफटॉप एण्ड स्मॉल सोलर ग्रिड इन्टरैक्टिव सिस्टम्स) रेग्यूलेशन, 2015 के अधीन स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से,

जनित ऊर्जा के उपभोग पर उसके द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क के संदाय से इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 01.4.2018 से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है कि संगृहीत या प्रभारित शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा और राज्य सरकार को निक्षिप्त शुल्क प्रतिदत्त नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.03.2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-26]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.47.-राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 09.03.2015 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "0.40 रुपये प्रति इकाई (किलो वाट प्रति घण्टा)", के स्थान पर अभिव्यक्ति "1.00 रुपये प्रति इकाई (किलो वाट प्रति घण्टा)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-27]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.48.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

- (i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,
- (ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में, और
- (iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारीया राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या प्राईवेट संस्था द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-28]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.49.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-13 दिनांक 31.05.2019 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 4, 5, 6, 7 और 8 तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और
- (ii) विद्यमान परन्तुक हटाये जायेंगे।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-29]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.50.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-14 दिनांक 31.05.2019 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और
- (ii) विद्यमान परन्तुक हटाये जायेंगे।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-30]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.51.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या विद्यार्थी, जो राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2015 के अधीन सहायता प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित दस लाख रुपये तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना 31.03.2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-31]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.52.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-32]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.53.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-33]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.54.-राजस्थानस्टाम्पअधिनियम, 1998 (1999 काअधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुए औरइसविभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-218 दिनांक 08.03.2016 कोअतिष्ठितकरतेहुए राज्य सरकार, यह राय होनेपरकिलोकहितमें ऐसाकियाजानासमीचीनहै, इसके द्वाराआदेशदेतीहैकिमाता या पिता द्वारा पुत्र या पुत्री के पक्ष में पैतृक सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित व्यवस्थापन की लिखतपरप्रभार्यस्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-34]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.55.-राजस्थानस्टाम्पअधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-217 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-35]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.56.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

- (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
- (ii) दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
- (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
- (iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ऐसे मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे

प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

2. ऐसे मामलों में, जहां कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व पहले ही निक्षिप्त करा दिया गया है, वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।
3. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क की कुल रकम इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।
4. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन निक्षिप्त रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्दे समायोजित की जायेगी।
5. उपर्युक्त मामलों में पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अन्य रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-36]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.57.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

- (i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,
- (ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में, और
- (iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारीया राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या प्राईवेट संस्था द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, निदेशक,

सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-37]

राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.58.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विखण्डित करती है, अर्थात्:-

- (1) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1आर दिनांक 14.07.2014;
- (2) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/3एच दिनांक 01.03.2002;
- (3) अधिसूचनासंख्यांक एफ.6(252)परि/कर/एचक्यू/05/4जी-163दिनांक 09.03.2007;
- (4) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/15 दिनांक 31.03.1997; और
- (5) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/16सी दिनांक 24.03.2005

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.59.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-परिवहन यानों और परिवहन यानों पर संदेय एकबारीय कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	एकबारीय कर की दर
1	2	3
1.	इंजन क्षमता वाले परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले दो पहिया वाले यान।	
	(क) 200 सीसी तक	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) 200 सीसी से अधिक और 500 सीसी तक	यान की लागत का 13 प्रतिशत
	(ग) 500 सीसी से अधिक	यान की लागत का 15 प्रतिशत
2.	परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले तीन पहिया वाले यात्री यान	
	(क) तीन तक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 3,000/-
	(ख) चार की बैठक क्षमता के साथ	रु. 6,000/-
	(ग) चार से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 8,000/-
3.	इंजन क्षमता वाले 10 तक की बैठक क्षमता के साथ चार पहिया वाले गैर-परिवहन यान	
	(क) 800 सीसी तक	
	(i) पेट्रोल	यान की लागत का 6 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	
	(i) पेट्रोल	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 11 प्रतिशत
	(ग) 1200 सीसी से अधिक	
	(i) पेट्रोल	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 12 प्रतिशत
4.	तीन पहिया से अधिक वाले टैक्सी कैब/मैक्सी कैब/संविदा गाड़ी परमिट यान और पर्यटक परमिट यान	
	(क) तेरह तक की बैठक क्षमता के साथ	यान की लागत का 11 प्रतिशत
	(ख) तेरह से अधिक और बाईस तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 35 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 26 प्रतिशत
5.	माल यान	
	(क) संलग्न यान	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) 16500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) संलग्न यान से भिन्न	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) 3000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान की लागत का 10 प्रतिशत

	(iii) 3000 कि.ग्रा. से अधिक और 16500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 11 प्रतिशत
6.	उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले अन्य माल यान यथा डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बूलेंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्कड लैंडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स और फायर फाइटिंग यान, हीयर्सज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन आदि।	
	(क) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
7.	प्राइवेट सेवा यान	
	(क) 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
	(ख) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 35 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 25 प्रतिशत
8.	7 से अधिक और 10 तक की बैठक क्षमता के साथ शैक्षिक संस्था यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
9.	प्राइवेट उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
10.	रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउण्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई भी अन्य गैर-परिवहन यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 8 प्रतिशत
11.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 8.5 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7 प्रतिशत
12.	शुद्ध ऑफ-हाइवे यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 6 प्रतिशत
13.	माल यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले गैर-कृषिक ट्रेक्टर-ट्रेलर्स	ट्रेक्टर जिसमें ट्रेलर संलग्न है की लागत का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

- (i) ऊपर क्रम संख्यांक 1 और 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर की 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।
- (ii) ऊपर क्रम संख्यांक 9 से 11 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।
- (iii) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगा,-
 - (क) ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान का कब्जा उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम किया जा रहा हो; या
 - (ख) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम अन्तरित किया जा रहा हो।
- (iv) राज्य में या राज्य के बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।
- (v) ऐसे मामलों में जहां गैर-परिवहन यान या परिवहन यान के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर संदत्त कर दिया गया है और तत्पश्चात् यान का प्रवर्ग/वर्णन परिवर्तित हो जाता है, तब यान का स्वामी कर के अंतर की रकम संदत्त करेगा यदि प्रवर्ग/वर्णन में परिवर्तन के कारण कर की दर बढ़ जाती है किन्तु यदि प्रवर्ग/विवरण में परिवर्तन के कारण कर की दर कम होती है तो यान के स्वामी द्वारा किसी भी कर का संदाय नहीं करना होगा।
- (vi) यदि ऊपर क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते पाये जायें तो ये यान उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलना पाया गया था, एकबारीय कर की दर के 1/10 हिसाब से समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर संदत्त करने के दायी होंगे।

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण:

- (i) कर की संगणना के लिए यानों की लागत:-
 - (क) नये यान/चेसिस के मामले में, किसी भी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी भी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को छोड़कर, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा-दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।
 - (ख) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/क्रय किये गये और राजस्थान में समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान

के लिए, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्द होता है इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(ग) भारत से बाहर विनिर्मित यान के मामले में, भारत के परिक्षेत्र में इसके आयात के समय पर उद्गृहीत माल-भाड़े, करों और शुल्कों को सम्मिलित करते हुए भारतीय मुद्रा में क्रय कीमत होगी।

- (ii) "संनिर्माण उपस्कर यान" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रूट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क का वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नियमित रूप से उपयोग हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान का परिवहन यान होना समझा जायेगा।
- (iii) शुद्ध ऑफ-हाइवे यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो या तो संनिर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त किया गया है या किसी भी बंद परिसर, कारखाना अथवा खान में उपयोग हेतु डिजाइन किया हुआ और अनुकूलित हो और अपनी स्वयं की शक्ति के स्रोत से चलने हेतु सज्जित हो।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.60.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट राज्य में रजिस्ट्रीकृत या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-अस्थायी परमिट या अस्थायी परमिट पर चलने वाले यात्री यानों पर संदेय मोटर यान कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के भीतर या उप-नगरीय मार्गों या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियों को छोड़कर, स्कीम मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों) पर चलने वाली मंजिली	प्रति माह रु. 665/- प्रति सीट

	गाड़ियां	
2.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या, दोनों, के क्षेत्र के भीतर या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियों को छोड़कर उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत नहीं आने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(i) प्रतिदिन 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 300/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 560/- प्रति सीट
3.	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो	प्रति माह रु. 130/- प्रति सीट
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक हो	प्रति माह रु. 140/- प्रति सीट
4.	अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) 26 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 4000/-
	(ख) 26 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 5000/-
	(ग) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 10000/-
5.	राजस्थान में अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाली अन्य राज्यों की मंजिली गाड़ियां	
	(i) प्रतिदिन 20 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति दिन रु. 25/-
	(ii) प्रतिदिन 20 कि.मी. से अधिक किन्तु 40 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 50/-
	(iii) प्रतिदिन 40 कि.मी. से अधिक किन्तु 80 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 150/-
	(iv) प्रतिदिन 80 कि.मी. से अधिक किन्तु 120 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 225/-
	(v) प्रतिदिन 120 कि.मी. से अधिक किन्तु 160 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 300/-
	(vi) प्रतिदिन 160 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 400/-
	(vii) प्रतिदिन 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 500/-
	(viii) प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 700/-
6.	पारस्परिक करार से परे/उसके बिना अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यान	
	(क) 47 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 2.50 प्रति सीट
	(ख) 47 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1.50 प्रति सीट
7.	संविदा गाड़ी परमिटों (पर्यटन परमिटों से भिन्न) अस्थायी और गैर-अस्थायी दोनों परमिटों पर चलाये जा रहे यान, तथा इस राज्य के परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाये जा रहे यात्री यान	

	(क) गैर-अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 1000/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 875/- प्रति सीट
	(ख) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया वाले मोटर यान	प्रति दिन रु. 35/-
	(ग) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 40/-
	(ii) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 80/-
	(iii) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 400/-
	(iv) 22 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	
	(क) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं में चलने वालों से भिन्न गैर-अस्थायी मंजिली गाड़ी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान	प्रति दिन रु. 500/-
	(ख) उनसे भिन्न जो उपर्युक्त (क) के अधीन आते हैं	प्रति दिन रु. 800/-
8.	इस राज्य के पर्यटन परमिटों पर चलने वाले यान	
	(क) तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 1150/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 885/- प्रति सीट
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले स्लीपर कोच	प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट
9.	22 से अधिक की बैठक क्षमता वाले प्राइवेट सेवा यान	प्रति माह रु. 290/- प्रति सीट
10.	फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन यान	प्रति माह रु. 26250/- प्रति यान
11.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अधीन जारी किये गये परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के पर्यटन यान	
	(क) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/- प्रति सीट
	(ख) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/- प्रति सीट
	(ग) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 875/- प्रति सीट
	(घ) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- प्रति सीट
	(ङ) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- प्रति सीट
12.	राजस्थान राज्य में अस्थायी परमिट पर चलने वाले राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान	
	(क) तीन पहिया वाले यात्री यान	प्रति सप्ताह रु. 200/- प्रति सीट
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले यात्री यान	
	(i) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/- प्रति सीट
	(ii) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/- प्रति सीट
	(iii) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 900/- प्रति सीट
	(iv) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- प्रति सीट

	(v) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- प्रति सीट
13.	स्पेयर यान (किसी भी परमिट के अन्तर्गत नहीं आने वाला यान)	प्रति माह रु. 320/- प्रति सीट

परन्तु,-

- (i) क्रम संख्यांक 1 से 3 के अन्तर्गत आने वाली कोई मंजिली गाड़ी यदि मोटरयान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से अन्यथा किसी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ियों के उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से अतिरिक्त विशेष सड़क कर संपूर्ण मास के लिए संदत्त करने की दायी होगी।
- (ii) क्रम संख्यांक 1 से 3 और 7 से 9 में विनिर्दिष्ट, नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा।
- (iii) क्रम संख्यांक 7 के स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाले मोटर यान के मामले में कर अधिकतम 14000/- रुपये प्रति माह संदेय होगा।
- (iv) क्रम संख्यांक 7 के स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यान के मामले में कर अधिकतम 14000/- रुपये प्रति माह संदेय होगा।
- (v) यदि उपर्युक्त परन्तुक (iv) में विनिर्दिष्ट कोई यान, समुचित परमिट के बिना चलता हुआ पाया जाता है तो वह क्रम संख्यांक 1 के सामने यथा-विनिर्दिष्ट कर का दो गुना संपूर्ण माह के लिए अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (vi) यदि 10 से अधिक की बैठक क्षमता वाला यात्री यान किसी विधिमान्य परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता पाया जाता है तो वह यान क्रम संख्यांक 1 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर संपूर्ण माह के लिए अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: स्लीपर कोच की बैठक क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बर्थ 2 सीट के बराबर मानी जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.61.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट,राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों, अस्थायी परमिटों पर चल रहे अन्य राज्य के माल यानों, संनिर्माण उपस्कर यानों, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यानों या मोटर यानों के चेसिस पर और पारस्परिक करार के अधीन जारी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानोंपर संदेय मोटर यान कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1.	राज्य के माल यान (क) तीन पहियों से अधिक वाले यान	
	(i) 16500 कि.ग्रा. से अधिक और 25000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 950/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ii) 25000 कि.ग्रा. से अधिक और 45000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 750/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iii) 45000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. से अधिक	रु. 625/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ख) उपरोक्त प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई अन्य परिवहन यान या यान जैसे कि डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, टिप्पर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बूलेंस, एनीमल एम्बूलेंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्कड लैंडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स और फायर फाइटिंग यान, हीयर्सज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन आदि	

	(i) 16500 कि.ग्रा. से अधिक और 25000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 950/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ii) 25000 कि.ग्रा. से अधिक और 45000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 750/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iii) 45000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. से अधिक	रु. 625/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ग) माल यानों के रूप में उपयोग किये जाने वाले ओवर डायमेंशन कैरियर ट्रेलर	रु. 50000/- प्रतिवर्ष
2.	पारस्परिक करार के अधीन जारी किये गये परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 9000 कि.ग्रा. तक के भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 500/- रु. प्रतिवर्ष
	(ii) 9000 कि.ग्रा. से अधिक भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 800/- रु. प्रतिवर्ष
3.	राज्य में अस्थायी परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 6000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 200/- रु.
	(ii) 6000 कि.ग्रा. से अधिक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 160/- रु.
4.	इस राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए आने वाले अन्य राज्यों के संनिर्माण उपस्कर यान	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. आर.एल.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 1000/- रु.
5.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यान या मोटर यानों के चेसिस।	
	(क) मोटर कार, ट्रैक्टर, ड्राइवर को छोड़कर 10 तक की बैठक क्षमता वाली ओमनी बस और सभी तीन पहिया वाले यान	प्रति यान 200/- रु.
	(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई भी अन्य मोटर यान	प्रति यान 1500/- रु.
	(ग) मोटर यानों के चेसिस	प्रति चेसिस 1000/- रु.

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजन या अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. के प्रयोजन के लिए, ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी भी अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/4]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.62.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 4-ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/कर/मु./09/26कदिनांक 11.10.2017को अतिष्ठित करते हुए राज्‍य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट मोटर यानों के वर्ग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय कर पर अधिभार की दर, उसके स्तम्भ संख्यांक 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर, इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यानों के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	एकबारीय कर का संदाय करने वाले यान	संदेय कर का 12.5 प्रतिशत
2.	एकबारीय कर से भिन्न कर का संदाय करने वाले यान	संदय कर का 6.25 प्रतिशत

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/5]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019**

एस.ओ.63.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्‍य सरकार, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4ख और 4ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) यदि कर,-

(i) एकबारीय कर के रूप में संदत्त किया जाना है,-

(क) जब गैर-परिवहन यान और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित परिवहन यान क्रय किया जाता है या राज्य के भीतर लाया जाता है, तब यान के क्रय या राज्य के भीतर लाये जाने से 30 दिन के भीतर या राज्य में यान के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन की तारीख को, जो भी पहले हो,; और

(ख) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित और 01.04.2007 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों की दशा में, ऐसी अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर;

(ii) वार्षिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

(iii) अर्द्धवार्षिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

(iv) त्रैमासिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर और 10 जनवरी को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा; और

(v) मासिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक मास के सातवें दिन को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

परन्तु फ्लीट स्वामी की दशा में, प्रत्येक मास के अंतिम दिन या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा।";

(iii) विद्यमान खण्ड (कक) और खण्ड (ककक) हटाये जायेंगे;

(iv) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग), (गग) और (घ) के अधीन कर:-

(i) व्यवहारियों/विनिर्माताओं/बॉडी निर्माताओं/वित्तपोषकों के कब्जे वाले यानों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(ii) कुल मिलाकर 22 से अधिक की बैठक क्षमता वाली चौपहिया संविदा गाड़ियों के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा। तथापि, कर, दो या अधिक मास के लिए अग्रिम रूप से संदत्त किया जा सकेगा;

(iii) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(iv) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों जिनमें फ्लीट स्वामी और अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले अन्य

राज्यों के यान सम्मिलित हैं, के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा। तथापि, कर, दो या अधिक मासों के लिए अग्रिम रूप से संदत्त किया जा सकेगा;

- (v) मंजिली गाडियों को छोड़कर अन्य राज्यों के ऐसे यान, जो अस्थायी परमिट पर या तो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 83 के अधीन या मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 के अधीन जारी किये गये किसी विधिमान्य प्राधिकार से अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन मंजूर किये गये किसी पर्यटक परमिट पर चल रहे हों, राजस्थान राज्य में प्रवेश के समय या उससे पूर्व कर की संपूर्ण रकम संदत्त करेंगे। इस उप-खण्ड के अधीन संदेय कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कर संग्रहण केन्द्र पर संदत्त किया जायेगा किन्तु ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, कर राज्य में प्रवेश करने से पूर्व केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदत्त किया जायेगा;
- (vi) इस राज्य के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अस्थायी परमिट पर चलने वाले यानों के संबंध में परमिट जारी करने के समय, राजस्थान राज्य में उपयोग की उस संपूर्ण कालावधि, जिनके लिए परमिट अभिप्राप्त किया गया है, के लिए संदत्त किया जायेगा;
- (vii) अन्य राज्यों द्वारा जारी और इस राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्थायी परमिट पर चलने वाली मंजिली गाडियों के संबंध में, प्रतिहस्ताक्षर करते समय संपूर्ण कालावधि के लिए अग्रिम रूप में संदत्त किया जायेगा;
- (viii) पारस्परिकता के अधीन और इस राज्य के प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में राज्य में प्रवेश के समय पर संग्रहण केन्द्र/जांच चौकी पर वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;
- (ix) किसी भी गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत नहीं आने वाले यात्री यानों के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा;
- (x) ऊपर उल्लिखित से भिन्न परिवहन यानों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा:

परन्तु ऐसे माल यानों, जो धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित से भिन्न हों, के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कर चालू वित्तीय वर्ष के मार्च मास की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदत्त किया जायेगा;

- (xi) किसी अस्थायी कालावधि के लिए राजस्थान में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के संनिर्माण उपस्कर यान या राज्य से होकर गुजरने वाले नये चेसिस/यान या अस्थायी कालावधि के लिए राजस्थान में प्रवेश करने वाले और अस्थायी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानों के संबंध में राज्य में प्रवेश के समय या उसके पूर्व अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा। इस उप-खण्ड के अधीन संदेय कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कर संग्रहण केन्द्र पर संदत्त किया जायेगा, किन्तु ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, कर राज्य में प्रवेश करने से पूर्व केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही संदत्त किया जायेगा;

- (v) विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा;
- (vi) खण्ड (ङ) में,-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ii) चतुर्थ परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4और 4ख के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vii) खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/6 दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा या किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाडियों पर विशेष सड़क कर की दर से संबंधित विद्यमान अधिसूचना के अधीन यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम की धारा 4ख के अधीन संदेय कर उस कालावाधि के लिए संदेय नहीं होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाडियों पर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संदेय कर उस कालावाधि के लिए संदेय नहीं होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (viii) विद्यमान खण्ड (छ) हटाया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एकमुश्त कर के मामले में प्ररूप एम.टी.ए.ए. में" हटायी जायेगी।

4. नियम 13 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13. परिवहन यान को कर की कम/अधिक रकम के दायित्वाधीन बनाने वाला परिवर्तन.- जब कभी किसी परिवहन यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि उक्त परिवर्तन के पश्चात् वह उस दर से जिस दर पर कर संदत्त किया जा चुका है, कम/अधिक दर पर, कर के दायित्वाधीन हो जाए, तो यान का स्वामी प्ररूप एम.टी.ए. में एक घोषणा करेगा और ऐसे यान के कर की पुनः संगणना के लिए कराधान अधिकारी को आवेदन करेगा। यदि कराधान अधिकारी का समाधान हो जाये कि यान में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है, जिससे वह जो कर संदत्त कर दिया गया उससे कम/अधिक कर की रकम के लिए दायी हो गया है तो वह उक्त तारीख से समुचित कम/अधिक कर की रकम पर यान का कर निर्धारण करेगा और उसका स्वामी ऐसी तारीख से इस प्रकार कम/अधिक किया गया कर संदत्त करेगा।"

5. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जब धारा 4(1)(ख)/4(1)(ङ) के अधीन एकबारीय कर और धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जब धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसने धारा 4(1)(ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एकमुश्त कर" हटायी जायेगी; और
- (iv) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

6. नियम 25 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 25 के उप-नियम (3) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और विशेष सड़क कर, जो देय हो गया है", के स्थान पर अभिव्यक्ति ", जो देय हो गया है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 26-क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 26-क में,-

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति ", एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;

(ii) उप-नियम (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4(1)(ख)/4(1)(ड) के अधीन एकबारीय कर और धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "या इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतरगैर-परिवहन यान से परिवहन यान में संपरिवर्तित कर दिया गया है" हटायी जायेगी; और

(iii) उप-नियम (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "या उसे उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतरपरिवहन यान से गैर-परिवहन यान में संपरिवर्तित कर दिया गया है" हटायी जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "या परिवहन यान से गैर-परिवहन यान में संपरिवर्तित किया गया था" हटायी जायेगी।

8. नियम 26-ख का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 26-ख के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और एकमुश्त कर" हटायी जायेगी।

9. नियम 41 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 41 के स्थान पर निम्नलिखितप्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"41. सीटों की संगणना.- जहां कर की संगणना सीटों की संख्या के आधार पर की जानी है वहां अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संदेय कर की दशा में ड्राइवर की सीट अपवर्जित की जायेगी।"

10. नियम 42 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 42 के स्थान पर निम्नलिखितप्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"42. कर की संगणना के प्रयोजन के लिए कीमत.- यान/चेसिस कीकीमत,-

(क) नये यान/चेसिस के मामले में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, करों और उद्ग्रहणों के तत्वों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित क्रय कीमत होगी,

(ख) पुराने/उपयोग किये गये यान/चेसिस के मामलेमें कीमत, नये यानके समान प्रकार की वर्तमान कीमत पर निर्धारित की गयी कीमत के बराबर होगी:

परन्तु राज्य के बाहर क्रय किये गये या रजिस्ट्रीकृत यान या मिलीटरी डिस्पोजल वाले यानों के मामले में कीमत इस राज्य में समान प्रकार के यानों के लिए, तारीख जिसको कि कर शोध है, को लागू कीमत होगी।

स्पष्टीकरण: (i) जब इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (द) के अधीन एक से अधिक यान/चेसिस के साथ समानता साबित हो जाये, तब सबसे कम लागत वाले यान/चेसिस को कर की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जायेगा।

(ii) जहां तक संभव हो, उसी विनिर्माता के यान/चेसिस से समानताएं निकाली जायेंगी।"

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/6]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.64.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से अधिसूचित करती है कि राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट निम्नलिखित वर्गों के परिवहन यानों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर के स्थान पर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर संदेय होगा, अर्थात्:-

- (1) 16500 कि.ग्रा. तक सकल भार वाले तीन पहियों और तीन पहियों से अधिक वाले माल यानों के समस्त प्रवर्ग;
- (2) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले संविदा गाड़ी यानों के समस्त प्रवर्ग;
- (3) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले पर्यटक परमिट यानों के समस्त प्रवर्ग; और
- (4) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले सभी प्राइवेट सेवा यान।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/7]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.65.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./95/24ई दिनांक 11.10.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के क्रम संख्यांक 2 में,

- (i) स्तम्भ संख्यांक 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) की मद संख्यांक (क) के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान अंक "2000" के स्थान पर अंक "4000" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) स्तम्भ संख्यांक 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) की मद संख्यांक (ख) के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान अंक "2000" के स्थान पर अंक "5000" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/24एफ]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग**अधिसूचना**

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.66.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में दिनांक 10.07.2019 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान, जो केवल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.), कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन.जी.) या सौर ऊर्जा द्वारा चालित हैं और यान विनिर्माताओं द्वारा इसी रूप में मूल रूप से विनिर्मित हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय कर के 50 प्रतिशत की, इसके द्वारा छूट देती है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/8]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT**(TAX DIVISION)**

Jaipur, July 10, 2019

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(43)FD/Tax/2019-24 to 27, No.F.4(17)FD/Tax/2019-28 to 37 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/1 to 8 and F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/24F dated July 10, 2019.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.44.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendment in Schedule IV appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule IV appended to the said Act, in Part B, GOODS UNDER CATEGORY OF INDUSTRIAL INPUTS, the existing serial number 183 and entries thereto shall be deleted.

[No.F.12(43)FD/Tax/2019-24]
By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)
Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.45.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule VI appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule VI appended to the said Act, after the existing serial number 24 and entries thereto, the following new serial number 25 and entries thereto shall be added, namely:-

“

25.	Natural Gas in Liquefied or Gaseous state	10	
-----	-------------------------------------------	----	--

 ”

[No.F.12(43)FD/Tax/2019-25]
By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)
Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.46.-In exercise of the powers conferred by clause (3) of the proviso to section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No.12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with effect from 01.04.2018, from payment of electricity duty payable by a person on the consumption of energy generated by him within the State from,

- (i) solar power plants set up for his own use; and
- (ii) solar power plant set up under the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Net-Metering for Rooftop and Small Solar Grid interactive Systems) Regulations, 2015.

subject to the conditions that the duty collected or charged, if any, shall be paid to the State Government and that the duty deposited to the State Government shall not be refunded.

This notification shall remain in force upto 31.03.2020.

[No.F.12(43)FD/Tax/2019-26]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.47.-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-219 dated 09.03.2015, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression “Rupees 0.40 per unit (KWH)”, the expression “Rupees 1.00 per unit (KWH)” shall be substituted.

[No.F.12(43)FD/Tax/2019-27]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT**(TAX DIVISION)****NOTIFICATION**

Jaipur, July 10, 2019

S.O.48.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed or lease deed regarding residential flat or house executed by the State Government or local authority or any other authority of the State Government or gift deed regarding residential flat or house executed by any person or private institution,-

- (i) in favour of wife of martyr,
- (ii) if the wife of martyr is not alive, then in favour of either minor daughter or minor son, and
- (iii) if the martyr was unmarried, then in favour of either father or mother,

shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-28]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT**(TAX DIVISION)****NOTIFICATION**

Jaipur, July 10, 2019

S.O.49.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(60)FD/Tax/2012/pt.-13 dated 31.05.2019, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in table, the existing serial number 4, 5, 6, 7 and 8 and entries thereto shall be deleted; and
- (ii) the existing provisos shall be deleted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-29]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)****NOTIFICATION**

Jaipur, July 10, 2019

S.O.50.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(60)FD/Tax/2012/pt.-14 dated 31.05.2019, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in table, the existing serial number 6 and 7 and entries thereto shall be deleted; and
- (ii) the existing provisos shall be deleted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-30]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.51.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of loan upto rupees ten lakh executed for the purposes of establishment of Start-up by any individual, or group of individuals or students who are eligible to receive support under the Rajasthan Start-up Policy, 2015, shall be remitted.

This notification shall remain in force upto 31.03.2020.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-31]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.52.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-103 dated 08.03.2017, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "rupees five lakh", the expression "rupees twenty five lakh" shall be substituted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-32]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.53.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-104 dated 08.03.2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) for the existing expression "0.15 percent", the expression "0.25 percent" shall be substituted; and
- (ii) for the existing expression "rupees five lakh", the expression "rupees twenty five lakh" shall be substituted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-33]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.54.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-218 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of settlement regarding ancestral property executed by mother or father in favour of son or daughter, shall be remitted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-34]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.55.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-217 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of partition of ancestral property, shall be remitted.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-35]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)
Joint Secretary to Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2019**

S.O.56.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that,-

1. interest and penalty payable on stamp duty shall be remitted in the following cases, namely:-
 - (i) Cases pending before the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.
 - (ii) Cases filed before Collector (Stamps) during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019 in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.
 - (iii) Cases adjudicated by the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.
 - (iv) Cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court upto the date of this notification wherein party withdraws the case and submits the proof of such withdrawal and the stamp duty payable has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.

2. Cases where stamp duty adjudicated by the Collector (Stamps) has already been deposited before the date of this notification, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.
3. Cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court wherein the total amount of stamp duty payable has been deposited before the date of this notification and the party withdraws the case and submits the proof of such withdrawal, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 10.07.2019 to 30.09.2019.
4. The amount deposited under proviso to the section 65 of the said Act for filing revision before Rajasthan Tax Board, shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
5. In the aforesaid cases stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-36]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT

(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, July 10, 2019

S.O.57.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the conveyance deed or lease deed regarding residential flat or house executed by the State Government or local authority or any other authority of the State Government or gift deed regarding residential flat or house executed by any person or private institution,-

- (i) in favour of wife of martyr,
- (ii) if the wife of martyr is not alive, then in favour of either minor daughter or minor son, and
- (iii) if the martyr was unmarried, then in favour of either father or mother,

shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(17)FD/Tax/2019-37]

By Order of the Governor

(Bishnu Charan Mallick)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, July 10, 2019**

S.O.58.-In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, rescinds this department's following notifications, with immediate effect, namely:-

- (1) Notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1R dated 14.07.2014;
- (2) Notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002;
- (3) Notification number F.6(252)Pari/Tax/Hqrs/05/4G-163 dated 09.03.2007;
- (4) Notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/15 dated 31.03.1997; and
- (5) Notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/16C dated 24.03.2005.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/1]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, July 10, 2019**

S.O.59.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, specifies the rate of one time tax payable on non-transport vehicles and transport vehicles as specified in column number 2 of the table given below, at the rates specified against each of them in column number 3 of the said table, namely:-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of One Time Tax
1	2	3
1.	Two Wheeled Vehicles used as transport or non-transport vehicle having engine capacity.	
	(a) upto 200 cc	8% of the cost of the vehicle.
	(b) more than 200 cc and upto 500 cc	13% of the cost of the vehicle.
	(c) more than 500 cc	15% of the cost of the vehicle.

2.	Three Wheeled Passenger Vehicles used as Transport or Non-Transport Vehicle.	
	(a) with seating capacity upto three	Rs. 3,000/-
	(b) with seating capacity four	Rs. 6,000/-
	(c) with seating capacity more than four	Rs. 8,000/-
3.	Four Wheeled Non-Transport Vehicle with seating capacity upto 10 having engine capacity	
	(a) upto 800 cc	
	(i) petrol	6% of the cost of the vehicle
	(ii) diesel	8% of the cost of the vehicle
	(b) more than 800 cc and upto 1200 cc	
	(i) petrol	9% of the cost of the vehicle
	(ii) diesel	11% of the cost of the vehicle
	(c) more than 1200 cc	
	(i) petrol	10% of the cost of the vehicle
	(ii) diesel	12% of the cost of the vehicle
4.	More than Three Wheeled Taxi cab/Maxi cab/Contract Carriage Permit Vehicle and Tourist Permit Vehicle.	
	(a) with seating capacity upto 13	11% of the cost of the vehicle
	(b) with seating capacity more than 13 and upto 22	
	(i) purchased as chassis	35% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	26% of the cost of the vehicle.
5.	Goods Vehicle	
	(a) Articulated Vehicle	
	(i) Three Wheeled Vehicle	9% of the cost of the vehicle/ chassis.
	(ii) More than Three Wheeled Vehicle having GVW upto 16500 k.g.	10% of the cost of the vehicle/ chassis.
	(b) Other than Articulated Vehicle	
	(i) Three Wheeled Vehicle	9% of the cost of the vehicle.
	(ii) More than Three Wheeled Vehicle having G.V.W. upto 3000 k.g.	10% of the cost of the vehicle.
	(iii) More than Three Wheeled Vehicle having G.V.W. more than 3000 k.g. and upto 16500 k.g.	11% of the cost of the vehicle/ chassis.

6.	Other Goods Vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper Vans/Trailers, Cash Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumpers, Mobile Workshop, Ambulance, Fire Tenders, Snorked ladders, Auxiliary Trailers, Fire Fighting Vehicles, hearses, Mail Carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans etc.	
	(a) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(b) purchased with a complete body	7.5% of the cost of the vehicle.
7.	Private Service Vehicles	
	(a) with seating capacity upto 13	
	(i) purchased as a chassis	15% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	12% of the cost of the vehicle.
	(b) with seating capacity more than 13 and upto 22	
	(i) purchased as a chassis	35% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	25% of the cost of the vehicle.
8.	Educational Institutional vehicle with seating capacity more than 7 and upto 10	
	(i) purchased as a chassis	15% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	12% of the cost of the vehicle.
9.	Camper Van/Trailer for private use	
	(i) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	7.5% of the cost of the vehicle.
10.	Vehicles fitted with Equipments like Rig, Generator, Compressor, Crane Mounted Vehicle, Fork Lift, Tow Trucks, Breakdown Van, Recovery Vehicles, Tower Wagon, tree trimming vehicles or any other Non-Transport Vehicle not covered under any category:	
	(i) purchased as a chassis	10% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	8% of the cost of the vehicle.

11.	Construction Equipment Vehicle	
	(i) purchased as a chassis	8.5% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	7% of the cost of the vehicle.
12.	Purely Off Highway Vehicle	
	(i) purchased as a chassis	7.5% of the cost of the chassis.
	(ii) purchased with a complete body	6% of the cost of the vehicle.
13.	Non-Agricultural Tractor-Trailers used as Goods Vehicle	1 % of the cost of the tractor to which the Trailer is attached.

Provided that,-

- (i) On every transfer of ownership of non-transport motor vehicles mentioned in column number 2 against serial number 1 and 3 above, an additional one time tax at the rate of 25% of the onetime tax paid at the time of registration or after registration shall be payable.
- (ii) On every transfer of ownership of non-transport motor vehicles mentioned in column number 2 against serial number 9 to 11 above, an additional one time tax at the rate of 10% of the onetime tax paid at the time of registration or after registration shall be payable.
- (iii) No additional tax shall be payable,-
 - (a) in case where transfer of ownership is being done in the name of person succeeding to the possession of the motor vehicle owing to the death of the registered owner of the motor vehicle; or
 - (b) in case where the vehicle is transferred in the name of the insurance company on account of settlement of the claim filed by the owner against the insurance company.
- (iv) In case of vehicles already registered in or outside the state or in case of military disposal vehicles, on which One time tax was not payable earlier, the Onetime tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above, at the rate of 5 % per financial year or part thereof upto 15 years from the date of registration.
- (v) In case where One time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Act for non-transport vehicle or transport vehicle has been paid and thereafter the category/description of the vehicle changes, the vehicle owner shall have to pay difference of tax if change in category/description leads to higher rate of tax but if change in category/description leads to lower rate of tax the vehicle owner has not to pay any tax.
- (vi) If vehicles, as mentioned in column number 2 against serial number 3 above, are found plying on hire or reward, then these vehicle shall be liable to pay tax as notified for transport vehicles of similar type at one tenth the rate of one time tax, for the financial year in which the vehicle was found on hire or reward.

Note- In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as was payable under the Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation:

- (i) The cost of the vehicle for the computation of tax:-
 - (a) In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacture or dealer.
 - (b) In case of vehicle registered/purchased outside the State and brought in Rajasthan for assignment/registration and for the vehicles already registered in Rajasthan on which one time tax was not payable earlier, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on the day when the tax becomes due on similar type of the vehicle in this State.
 - (c) In case of vehicle manufactured out of India, shall be the purchase price in Indian currency including freight, taxes and duties levied at the time of its import into the territory of India.
- (ii) "Construction Equipment Vehicle" shall mean a vehicle as defined in rule 2(ca) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The use of public road by Construction Equipment Vehicle is incidental to the main off-route function. If the public road is being used regularly for carrying on commercial activities, then Construction Equipment Vehicle shall be deemed to be a Transport Vehicle.
- (iii) Purely-off highway vehicle means a motor vehicle either used as a Construction Equipment Vehicle or designed and adapted for use in any enclosed premises, factory or mine, equipped to travel on its own sources of power.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/2]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 10, 2019

S.O.60.-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, specifies the rate of motor vehicle tax payable on Passenger Vehicles registered in the State or registered in other State and plying on non-temporary permit or temporary permit as specified in column number 2 of

the table given below, at the rates specified against each of them in column number 3 of the said table, namely :-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of Tax
1	2	3
1	Stage Carriage plying on scheme routes (nationalized routes) excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of municipality or urban improvement trust or both or sub-urban routes or rural routes	Rs. 665 per seat per month
2	Stage Carriage not covered under serial number 1 above excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of municipality or urban improvement trust or both or rural routes	
	(i) plying upto 300 k.m. per day	Rs. 300/- per seat per month
	(ii) plying more than 300 k.m. per day	Rs. 560/- per seat per month
3	Stage Carriage plying on rural routes	
	(a) distance required to be covered by the service in a day upto 200 k.m.	Rs. 130/- per seat per month
	(b) distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 k.m.	Rs. 140/- per seat per month
4	Stage Carriage plying exclusively within Municipality/ Urban Improvement Trust limits	
	(a) with seating capacity upto 26	Rs. 4000/- per year
	(b) with seating capacity more than 26 and upto 32	Rs. 5000/- per year
	(c) with seating capacity more than 32	Rs. 10000/- per year
5	Stage Carriage of other States plying on interstate routes in Rajasthan	
	(i) plying upto 20 k.m. per day	Rs. 25/- per day
	(ii) plying exceeding 20 k.m. but not exceeding 40k.m. per day	Rs. 50/- per day
	(iii) plying exceeding 40 k.m. but not exceeding 80k.m. per day	Rs. 150/- per day
	(iv) plying exceeding 80 k.m. but not exceeding 120k.m. per day	Rs. 225/- per day
	(v) plying exceeding 120 k.m. but not exceeding 160k.m. per day	Rs. 300/- per day
	(vi) plying exceeding 160 k.m. but not exceeding 240k.m. per day	Rs. 400/- per day

	(vii) plying exceeding 240 k.m. but not exceeding 400k.m. per day	Rs. 500/- per day
	(viii) plying over 400 k.m. per day	Rs. 700/- per day
6	Transport vehicles of other State plying on interstatel routes beyond/without reciprocal agreement	
	(a) with seating capacity upto 47	Rs. 2.50 per seat per day
	(b) with seating capacity more than 47	Rs. 1.50 per seat per day
7	Vehicles plying on contract carriage permits (other than tourist permits) both temporary and non-temporary permits, and on passenger vehicles plying on hire or reward without permit of this State	
	(a) more than three wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits	
	(i) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 1000/- per seat per month
	(ii) with seating capacity more than 32	Rs. 875/- per seat per month
	(b) three wheeled motor vehicles plying on temporary permits	Rs. 35/- per day
	(c) more than three wheeled motor vehicles plying on temporary permits	
	(i) with seating capacity upto 6	Rs. 40/- per day
	(ii) with seating capacity more than 6 and upto 13	Rs. 80/- per day
	(iii) with seating capacity more than 13 and upto 22	Rs. 400/- per day
	(iv) with seating capacity more than 22	
	(a) Motor Vehicles covered by non-temporary stage carriage permits other than those plying exclusively within the Municipal limits	Rs. 500/- per day
	(b) other than those covered under (a) above	Rs. 800/- per day
8	Vehicles plying on tourist permits of this state	
	(a) more than three wheeled motor vehicles	
	(i) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 1150/- per seat per month
	(ii) with seating capacity more than 32	Rs. 885/- per seat per month
	(b) more than three wheeled sleeper coaches	Rs. 510/- per seat per month
9	Private Service Vehicles with seating capacity more than 22	Rs. 290/- per seat per month
10	Vehicles owned by a fleet owner	Rs. 26250/- per month per vehicle

11	Tourist Vehicles of other States plying on permits issued under section 88(9) of the Motor Vehicles Act, 1988	
	(a) with seating capacity upto 6	Rs. 160/- per seat per day
	(b) with seating capacity more than 6 and upto 13	Rs. 210/- per seat per day
	(c) with seating capacity more than 13 and upto 22	Rs. 875/- per seat per day
	(d) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 1000/- per seat per day
	(e) with seating capacity more than 32	Rs. 1600/- per seat per day
12	Vehicle registered outside the State plying on temporary permit in the State of Rajasthan	
	(a) three wheeled passenger vehicles	Rs. 200/- per seat per week
	(b) more three wheeled passenger Vehicles	
	(i) with seating capacity upto 6	Rs. 160/- per seat per day
	(ii) with seating capacity more than 6 and upto 13	Rs. 210/- per seat per day
	(iii) with seating capacity more than 13 and upto 22	Rs. 900/- per seat per day
	(iv) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 1000/- per seat per day
	(v) with seating capacity more than 32	Rs. 1600/- per seat per day
13	Spare vehicle (vehicle not covered under any permit)	Rs. 320/- per seat per month

Provided that,-

- (i) if any stage carriage falling under serial number 1 to 3, is found plying any trip other than trip/trips allowed to it under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under, then such stage carriages shall be liable to pay additional tax for the entire month at the rate specified against the category for which it is allowed for plying.
- (ii) in case of vehicles specified in serial number 1 to 3 and 7 to 9, obtaining the fresh permits, the tax shall be payable from the date of issue of permits on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit.
- (iii) in case of the motor vehicle falling under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) in column number 2 of serial number 7 and plying exclusively within the Municipal/UIT limits, the tax shall be payable to a maximum of Rs. 14000/- per month.
- (iv) in case of the motor vehicle falling under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) in column number 2 of serial number 7 and plying exclusively under a non-temporary fix contract with any industrial or commercial entity the tax shall be payable to a maximum of Rs. 14000/- per month.

- (v) if any vehicle specified in proviso (iv) above, is found plying without appropriate permit it shall be liable to pay additional tax for entire month, two times of tax as specified against serial number 1.
- (vi) if a passenger vehicle having seating capacity more than 10 is found plying on hire or reward without any valid permit, the vehicle shall be liable to pay additional tax for the entire month at the rate specified against serial No. 1.

Note- In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as it was payable under the Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation: For the purpose of computation of the seating capacity of the sleeper coach, each berth shall be treated equal to 2 seats.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 10, 2019

S.O.61.-In exercise of the powers conferred by clause (a), clause (c) and clause (cc) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, specifies motor vehicle tax payable on Goods Vehicles registered in the State, Goods Vehicles of other State plying on temporary permits, Construction Equipment Vehicles, motor vehicles or chassis of motor vehicles registered temporarily and passing through the State and Goods Vehicles of other States plying on permit issued under reciprocal agreement, as specified in column number 2 of the table given below, at the rates specified against each in column number 3 thereof, namely :-

Table

S.No.	Description of Class of Motor Vehicle	Rate of Tax
1	2	3
1	Goods Vehicle of the State	
	(a) more than Three Wheeled Vehicle	
	(i) G.V.W. more than 16500 k.g. & upto 25000 k.g.	Rs. 950/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year
	(ii) G.V.W. more than 25000 k.g. & upto 45000 k.g.	Rs. 750/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year

	(iii) G.V.W. more than 45000 k.g.	Rs. 625/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year
	(b) any other transport vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper vans/Trailers, Tipper, Cash Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumper, Mobile Work Shops, Ambulance, Animal Ambulance, Fire Tenders, Snorked Ladders, Auxiliary Trailers and Fire Fighting Vehicles, Hearses, Mail carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans, etc.	
	(i) G.V.W. more than 16500 k.g. & upto 25000 k.g.	Rs. 950/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year
	(ii) G.V.W. more than 25000 k.g. & upto 45000 k.g.	Rs. 750/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year
	(iii) G.V.W. more than 45000 k.g.	Rs. 625/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof per year
	(c) Over dimension carrier trailer used as goods vehicles	Rs. 50000/- per year
2	Goods Vehicle of other States plying on permit issued under reciprocal agreement.	
	(i) with load carrying capacity upto 9000 k.g.	Rs. 500/- per 1000 k.g. or part thereof yearly
	(ii) with load carrying capacity above 9000 k.g.	Rs. 800/- per 1000 k.g. or part thereof yearly
3	Goods Vehicle of other States plying on temporary permits in the state.	
	(i) G.V.W. up to 6000 k.g.	Rs. 200/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof for 30 days or part thereof
	(ii) G.V.W. more than 6000 k.g.	Rs. 160/- per 1000 k.g. of G.V.W. or part thereof for 30 days or part thereof
4	Construction Equipment Vehicles of other States coming for temporary use in this State.	Rs. 1000/- per 1000 k.g. of R.L.W. or part thereof for 30 days or part thereof
5	Motor Vehicles or chassis of Motor Vehicles registered temporarily and passing through the State.	
	(a) Motor car, Tractor, Omni Bus with seating capacity upto 10 excluding driver and all three wheeled vehicles	Rs. 200/- per vehicle
	(b) Any other Motor Vehicles not covered under clause(a)	Rs. 1500/- per vehicle

	(c) Chassis of Motor Vehicles	Rs. 1000/- per chassis
--	-------------------------------	------------------------

Note- In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor Vehicle, any tax or penalty as was payable under the said Act for any period prior to the coming into force of this notification.

Explanation: For the purpose of G.V.W./R.L.W. of Truck, Trailers or any combination or adaption thereof, including the articulated vehicles, the G.V.W./R.L.W. of the Truck/horse trailer and any adaption together shall be taken in consideration for computation of tax thereon.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/4]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 10, 2019

S.O.62.-In exercise of the powers conferred by section 4-E of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/26A dated 11.10.2017, the State Government hereby prescribes the rate of surcharge on the tax payable under section 4 of the said Act for class of motor vehicles as specified in column number 2 of the table given below, at the rate specified against each in column number 3 thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Description of Class of Motor Vehicles	Rate of Surcharge
1	2	3
1	Vehicles paying one time tax	12.5 % of the tax payable
2	Vehicles paying tax other than one time tax	6.25 % of the tax payable

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/5]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, July 10, 2019**

S.O.63.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing expression "section 4, 4B and 4C", the expression "section 4" shall be substituted;

(ii) the existing clause (A) shall be substituted by the following, namely:-

"(A) If the tax is to be paid,-

(i) as a one time tax,-

(a) when the non transport vehicle and transport vehicle notified under clause (b) of sub-section (1) of section 4 is purchased or brought into State, within 30 days of purchase of vehicle or bringing the vehicle into the State or on the date of registration or assignment of the vehicle in the State, whichever is earlier; and

(b) in case of transport vehicles notified under clause (b) of sub-section (1) of section 4 and registered before 01.04.2007, within 30 days from the date of such notification;

(ii) Yearly, it shall be paid on or before 30th day of April of each year;

(iii) Half yearly, it shall be paid on or before 15th of October and 15th of April of each year;

(iv) Quarterly it shall be paid on or before 10th of April, 10th of July, 10th of October and 10th of January of each Year; and

(v) Monthly, it shall be paid on or before 7th day of each month:

Provided that in case of fleet owner it shall be paid on or before last day of each month.";

(iii) the existing clause (AA) and clause (AAA) shall be deleted;

(iv) the existing clause (B) shall be substituted by the following, namely:-

"(B) The tax under clause (a), (c), (cc) and (d) of sub section (1) of section 4 of the Act in respect of:-

- (i) vehicles possessed by dealers/manufacturers/body builders/financiers shall be paid annually;
- (ii) four wheeled contract carriages having seating capacity above 22 in all shall be paid monthly. However the tax may be paid for two or more months in advance;
- (iii) stage carriages plying exclusively within municipal limits shall be paid yearly.
- (iv) stage carriages other than those plying exclusively within municipal limits including fleet owner and vehicles of other states plying on interstatal routes shall be paid monthly. However, the tax may be paid for two or more months in advance;
- (v) Vehicles of other States excluding stage carriages, plying on temporary permit or on a Tourist permit granted under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Transport Authorities of other States with a valid authorization issued either under rule 83 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or under Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 shall pay full amount of tax at the time of entry in the State of Rajasthan or before. Tax payable under this sub-clause shall be paid electronically or at Tax Collection Center but from such date as may be notified by the State Government, tax shall be paid only through electronic mode before entering in the State;
- (vi) Vehicles plying on temporary permit issued by the authorities of this State shall be paid at the time of issuance of permit for the entire period of use in the State of Rajasthan for which the permit is obtained;
- (vii) Stage carriages plying on temporary permits issued by other States and countersigned by this State shall be paid in advance for the entire period at the time of countersignatures;

(viii) Goods vehicles of other States under reciprocity and countersigned by the authorities of this State shall be paid yearly at the Tax Collection Centre/Check Post at the time of entry into the State;

(ix) Passenger vehicles not covered by any non-temporary permit shall be paid monthly;

(x) Transport vehicles other than mentioned above shall be paid yearly:

Provided that the tax for goods vehicle other than those notified under clause (b) of sub-section (1) of section 4 payable for the next financial year shall be paid in the month of March of current financial year on or before the 15th of March; and

(xi) Construction equipment vehicles of other states entering into Rajasthan for a temporary period, new chassis/vehicles crossing the state or goods vehicles of other states entering into Rajasthan for a temporary period and plying on temporary permit shall be paid in advance at the time of entering into state or before. Tax payable under this sub-clause shall be paid electronically or at Tax Collection Centre, but from such date as may be notified by the State Government, tax shall be paid only through electronic mode before entering in state.";

(v) the existing clause (D) shall be deleted;

(vi) in clause (E),-

(i) for the existing expression "under section 4B", the expression "under clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted; and

(ii) in forth proviso, for the existing expression "under section 4 and 4B", the expression "under clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;

(vii) in clause (F), for the existing expression "Tax under section 4B of the Act payable under notification No. F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/6, dated 31st March, 1997 or under the prevalent notification related to rate of special road tax on stage carriages of the state other than owned by a fleet owner shall not payable for the period", the expression "Tax payable under clause (a) of sub-section (1) of section 4 on stage carriages of the State other than owned by a fleet owner shall not be payable for the period" shall be substituted; and

(viii) the existing clause (G) shall be deleted.

3. Amendment of rule 6.- In sub-rule (1) of rule 6 of the said rules, the existing expression "in case of lump sum tax in form M.T.A.A.A." shall be deleted.

4. Substitution of rule 13.- The existing rule 13 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"13. Alteration of Transport vehicle making it liable to lower/higher amount of tax.- Whenever a transport vehicle is altered in such a way that after such alteration, it is liable to pay lower/higher amount of tax than the tax which has been paid, then owner of the vehicle shall make a declaration in form MTA and apply to the Taxation Officer for recomputation of tax of such vehicle. If the Taxation Officer is satisfied that the vehicle has been altered in such a way to make it liable to pay lower/higher amount of tax than the tax which has been paid he shall with effect from the date, assess the vehicle at appropriate lower/higher amount of tax and owner thereof shall thereupon pay with effect from the such date the tax as so reduced/ increased."

5. Amendment of rule 15.- In sub-rule (1) of rule 15 of the said rules,-

- (i) for the existing expression "when the one time tax under section 4(1)(b)/4(1)(e) and lump sum tax under section 4C", the expression "when the one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
- (ii) for the existing expression "one time tax under section 4(1)(e) or lump sum tax under section 4C, the expression "one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
- (iii) in clause (i), the existing expression "/lump sum tax " shall be deleted; and
- (iv) the existing proviso shall be deleted.

6. Amendment of rule 25.- In first proviso to sub-rule (3) of rule 25 of the said rules, for the existing expression "and special road tax which have become due have", the expression "which has become due has" shall be substituted.

7. Amendment of rule 26-A.- In rule 26-A of the said rules,-

- (i) in heading, the existing expression ", Lump sum tax" shall be deleted;
- (ii) in sub-rule (1),-
 - (a) for the existing expression "one time tax under section 4(1)(b)/4(1)(e) or lump sum tax under section 4C", the expression "one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted; and
 - (b) the existing expression "or has been converted into Transport Vehicle from Non-Transport Vehicle within five years from the date of its registration" shall be deleted; and

(iii) in sub-rule (2),-

- (a) the existing expression "or has been converted into Transport Vehicle from Non-Transport Vehicle within five years from the date of its registration" shall be deleted; and
- (b) the existing expression "or converted into Transport Vehicle from Non-Transport Vehicle" shall be deleted.

8. Amendment of rule 26-B.- In sub-rule (1) of rule 26-B of the said rules, the existing expression "and lump sum tax" shall be deleted.

9. Substitution of rule 41.- The existing rule 41 of the said rules shall be substituted, by the following, namely:-

"41.Computation of seats.- Wherever the tax is to be computed on the basis of number of seats, the seat of the driver shall be excluded in the case of tax payable under clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Act."

10. Substitution of rule 42.- The existing rule 42 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"42. Cost for the purpose of computation of tax.- Cost of vehicle/chassis shall be,

- (a) in case of new vehicle/chassis, purchase price as shown in purchase bill including the elements of taxes and levies, excluding discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer,
- (b) in case of old/used vehicle/chassis, cost shall be equal to the cost assessed at current price of similar type of new vehicle:

Provided that in case of vehicle purchased or registered outside the State or military disposal vehicles, cost shall be as applicable on the date on which the tax is due for the similar type of vehicle of this State.

Explanation: (i) When under clause (n) of sub-rule (1) of rule 2 of the these rules, similarity is established with more than one vehicle/chassis, then the vehicle/chassis having lowest cost shall be taken for the purpose of computation of tax.

- (ii) As far as possible, similarities shall be drawn from the vehicles/chassis of the same manufacturer."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/6]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, July 10, 2019**

S.O.64.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, with immediate effect, hereby notifies that in respect of following classes of Transport Vehicles registered or assigned in the State, one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 shall be payable instead of tax under clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the said Act, namely:-

- (1) all categories of three wheeled and more than three wheeled goods vehicles having gross vehicle weight upto 16500 kg;
- (2) all categories of contract carriage vehicles having seating capacity upto 22 in all;
- (3) all categories of tourist permit vehicles having seating capacity upto 22 in all; and
- (4) all private service vehicles having seating capacity upto 22 in all.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/7]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, July 10, 2019**

S.O.65.-In exercise of the powers conferred by section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/24E dated 11.10.2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, in serial number 2 of the Table,-

- (i) in column number 4 against item number (a) of sub-clause (ii) of clause (B) of column number 2, for the existing figure "2000", the figure "4000" shall be substituted; and

- (ii) in column number 4 against item number (b) of sub-clause (ii) of clause (B) of column number 2, for the existing figure "2500", the figure "5000" shall be substituted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/24F]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 10, 2019

S.O.66.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts 50% of tax payable under section 4 of the said Act on the vehicles registered in the State on or after 10.07.2019 that are driven solely by Liquefied Petroleum Gas (L.P.G.) or Compressed Natural Gas (C.N.G) or Solar Energy and originally manufactured by the vehicle manufacturers as such.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/8]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to Government